

भारत की अंतरकिष शक्तिक्रांति

यह एडटिलोरियल 01/01/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “[**Express View on ISRO's SpaDeX mission: A tryst in space**](#)” पर आधारित है। इस लेख में SpaDeX मिशन का उल्लेख किया गया है, जिसने भारत के विशिष्ट अंतरकिष-डॉकिंग क्लब में प्रवेश को चहिनति किया है और चंद्रयान-3 एवं आदतिय-1 की सफलताओं के बाद ISRO के वैश्वकि अग्रणी के रूप में उभरने पर प्रकाश डाला।

प्रलिमिस के लिये:

[भारत का अंतरकिष कार्यक्रम, SpaDeX, चंद्रयान-3, आदतिय-1, ISRO का NavIC, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, वक्रम-S, भारत का एंटी-सैटेलाइट \(ASAT\) परीक्षण, भारतीय अंतरकिष नीति 2023](#)

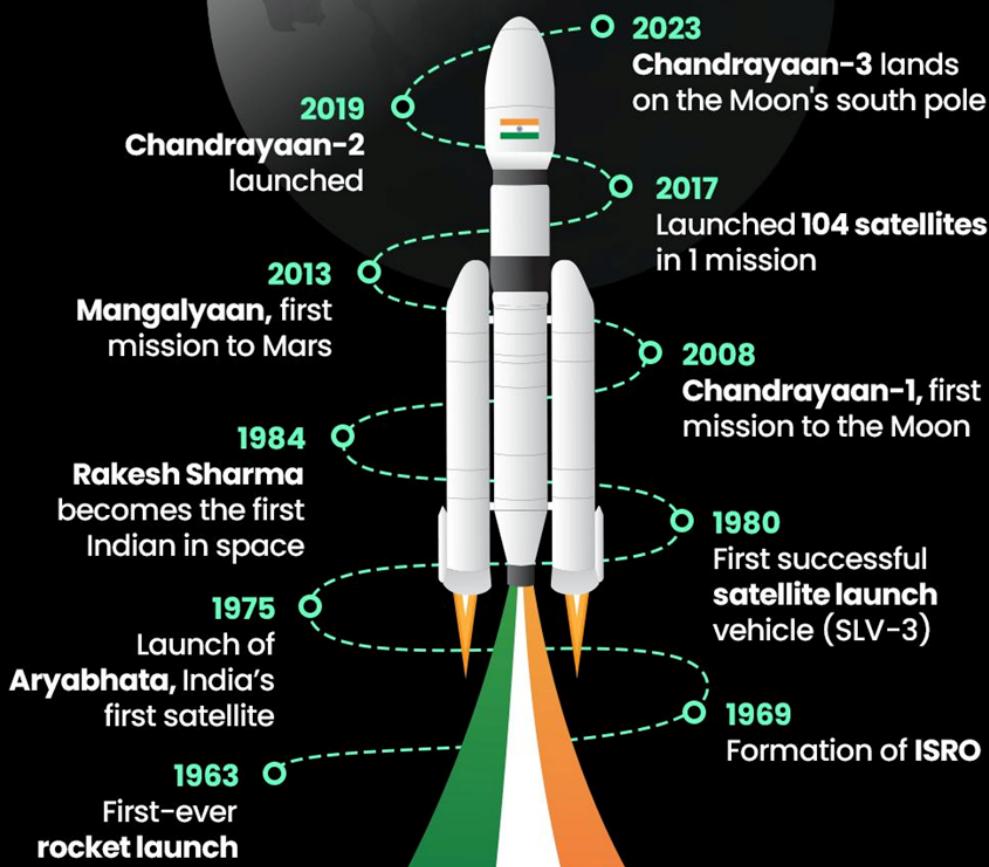
मेन्स के लिये:

भारत के अंतरकिष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे, भारत कसि प्रकार अपनी अंतरकिष-आधारित क्षमताओं को प्रबल कर रहा है।

ISRO के नवीनतम [SpaDeX](#) मिशन—स्पेस डॉकिंग का एक अग्रणी प्रयास जो भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ राष्ट्रों के एक विशिष्ट समूह में स्थान दिला सकता है, के साथ [भारत का अंतरकिष कार्यक्रम](#) परिषिकार के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह उपलब्धि वर्ष 2023 में [चंद्रयान-3](#) के सफल चंद्र लैंडिंग और [आदतिय-1](#) सौर मिशन के बाद आया है, जो ISRO के उपग्रह प्रक्षेपण एजेंसी से ग्रह अन्वेषण में अग्रणी बनने के लिये तेज़ी से विकास को दर्शाता है। अंतरकिष अन्वेषण के सभी पहलुओं में ISRO की बढ़ती विशेषज्ञता एवं वैश्वकि अंतरकिष शक्ति के रूप में उभरने की इसकी तत्परता का संकेत देती है, जो बरहमांड के संदरभ में मानवता की समझ हेतु महत्ततपूर्ण योगदान देने में सक्षम है।

//

MILESTONES IN INDIAN SPACE EXPLORATION



भारत अपनी अंतरकिष्य-आधारति क्षमताओं को कसि प्रकार प्रबल कर रहा है?

- इन-ऑर्बिट डॉकिंग और अंतरकिष्य स्टेशन विकास में नपिणता: हाल ही में ISRO द्वारा प्रक्षेपित भारत का SpaDeX मशिन (स्पेस डॉकिंग एक्सप्रेसिट) उन्नत अंतरकिष्य प्रौद्योगिकियों की ओर उसके कदम का उदाहरण है।
 - इस प्रयोग में दो उपग्रह, चेज़र और टार्गेट, शामिल हैं, जो स्वायत्त रूप से डॉकिंग कार्य करते हैं और ऑन-ऑर्बिट उपग्रह सर्वसिगि तथा संभावति भारतीय अंतरकिष्य स्टेशन को असेंबल करने जैसे भविष्य के मशिनों के लिये महत्त्वपूरण है।
 - यह ISRO के गगनयान कार्यक्रम का पूरक है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक मानव को अंतरकिष्य अन्वेषण के लिये भेजना है।
 - इस तरह की पहल भारत को उन चुनिदा देशों में शामिल करती है जो स्वायत्त डॉकिंग प्रौद्योगिकियों में महारत हासलि कर रहे हैं, तथा अंतर-ग्रहीय मशिनों के लिये इसके व्यापक नहितिरथ हैं।
- स्वदेशी उपग्रह तारामंडल को सुदृढ़ करना: भारत ने विदेशी डेटा पर नरिभरता कम करने के लिये घरेलू उपग्रह तारामंडल के नरिमाण को प्राथमिकता दी है।
 - 30 भारतीय कंपनियाँ रक्षा, बुनियादी अवसंरचना के प्रबंधन और मानचित्रण के लिये पृथक्की अवलोकन उपग्रह समूहों के नरिमाण एवं संचालन के लिये सहयोग कर रही हैं।
 - **ISRO का NavIC** उन्नयन का उद्देश्य भारत की नेविगेशन प्रणाली को उन्नत करना है ताकि वह GPS जैसे वैश्वकि समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सके।
 - यह पहल डेटा संप्रभुता को बढ़ावा देती है और महत्त्वपूरण बुनियादी अवसंरचना में आत्मनिर्भरता के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, तथा सार्वजनिक-नजिकी सहयोग को बढ़ावा देती है।

- लघु उपग्रह क्षमताओं और वैश्वकि प्रक्षेपण सेवाओं का वसितार: भारत का **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)**, नैनो उपग्रहों के प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करता है।
 - वर्ष 2031 तक अनुमानित 14 बलियन डॉलर के लघु उपग्रह बाजार का दोहन करके, भारत एक लागत प्रभावी वैश्वकि प्रतियोगी के रूप में उभरा है।
 - वर्ष 2023 में **PSLV-C56** मिशन ने कमरशिल पेलोड को सफलतापूर्वक तैनात किया, जो अंतरकिष्प प्रक्षेपण क्षेत्र में भारत की वशिवसनीयता को दर्शाता है।
 - इसके अतिरिक्त, SSLV विश्वविद्यालयों और स्टारटअप्स को प्रयोगात्मक उपग्रहों को तैनात करने में सक्षम बना रहे हैं, जिससे तकनीकी नवाचार में तेजी आ रही है।
- अंतरकिष्प स्टार्टअप पारस्थितिकी तंत्र और नजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना: वर्ष 2024 में स्वीकृत अंतरकिष्प स्टार्टअप के लिये 10 बलियन रुपए के फंड ने नजी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया है।
 - पक्सल और स्काईरूट एयरोस्पेस जैसी कंपनियाँ अरथ इमेजिंग एवं रॉकेट प्रौद्योगिकियों में क्रांति ला रही हैं, पक्सल ने हाइपरसैप्ट्रल उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है तथा स्काईरूट के **विक्रम-S** ने भारत का पहला नजी रॉकेट प्रक्षेपण किया है।
 - यह रणनीति उदयमशीलता की भागीदारी को बढ़ावा देती है, जिसके तहत 40 से अधिक स्टार्टअप भारत की अंतरकिष्प अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं।
- रक्षा और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों में प्रगति: **GSAT-7** जैसे रक्षा-उन्मुख उपग्रहों का प्रक्षेपण भारत की रणनीतिकी निशिरानी और संचार क्षमताओं को प्रबल करता है।
 - वर्ष 2019 में **भारत के एंटी-सैटेलाइट (ASAT) परीक्षण** ने अंतरकिष्प युद्ध के लिये इसकी तत्परता को प्रदर्शित किया, जैसे वर्ष 2020 से संचालित एक समर्पित **रक्षा अंतरकिष्प एजेंसी (DSA)** द्वारा प्रारंभित किया गया।
 - इससे उभरती सुरक्षा चुनौतियों, विशेषकर वैश्वकि शक्तियों द्वारा अंतरकिष्प के सैन्यीकरण के संदर्भ में, से निपटने में भारत की तैयारी सुनिश्चित होती है।
- रणनीतिकी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ और पहुँच: भारत अपनी वैश्वकि अंतरकिष्प स्थितिको बढ़ाने के लिये रणनीतिकी साझेदारियाँ बना रहा है।
 - अमेरिका स्थिति स्टार्टअप एक्ज़ाओम स्पेस, अंतरकिष्प स्टेशन मशिनों के लिये भारतीय रॉकेटों का उपयोग करने की योजना बना रहा है, जिससे भारत की लागत-कुशल प्रक्षेपण क्षमताओं का प्रदर्शन होगा।
 - जलवायु और ग्रह विज्ञान मशिनों के अंतरगत **NASA** और **ESA** के साथ सहयोग, जैसे कि **NISAR उपग्रह**, वैश्वकि चुनौतियों से निपटने में भारत की भूमिका को भी बढ़ावा देगा।
 - ऐसी साझेदारियाँ भारत की अंतरकिष्प महत्त्वाकांक्षाओं को भू-राजनीतिकी उद्देश्यों के साथ जोड़ती हैं, तथा सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देती है।
- अंतरकिष्प स्थिति और वैश्वकि योगदान को बढ़ाना: भारत स्थायी अंतरकिष्प प्रथाओं का पक्षधर रहा है, जैसा कि सौर अवलोकन के लिये आदतिय-**L1** जैसे मशिनों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसका उद्देश्य उपग्रहों पर अंतरकिष्प मौसम के प्रभावों को कम करना है।
 - इसके अतिरिक्त, भारत अंतरकिष्प स्थितिजागरूकता के लिये ISRO के **NETRA कार्यक्रम** के माध्यम से वैश्वकि मलबा प्रबंधन में योगदान दे रहा है।
 - विकास और संवहनीयता के बीच संतुलन बनाकर भारत **आरटेमसि अकॉरडस** जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप कार्य करता है, तथा बाह्य अंतरकिष्प में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देता है।
- चंद्र और अंतरग्रहीय अन्वेषण की खोज: वर्ष 2023 में भारत के चंद्रयान-3 की सफलता ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव अन्वेषण में भारत के प्रवेश को चहिनति किया, जो कबीलत कम देशों द्वारा प्राप्त की गई एक उपलब्धि है।
 - **शुक्रयान-1** द्वारा शुक्र ग्रह अन्वेषण के लिये ISRO की योजनाएँ अंतरग्रहीय अनुसंधान का नेतृत्व करने की इसकी महत्त्वाकांक्षा को दर्शाती हैं।
 - ये मशिन ग्रह विज्ञान में महत्त्वपूर्ण अंतरदृष्टिप्रदान करते हैं, जिससे वैश्वकि स्तर पर भारत की शैक्षणिकी और अनुसंधान साथ को बढ़ावा मिलता है।
- सामाजिक आरथिक लाभ के लिये अंतरकिष्प का उपयोग: अंतरकिष्प-आधारित सेवाएँ कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में प्रवर्तन ला रही हैं।
 - उदाहरण के लिये, **ISRO** का भुवन जयोपोर्टल आपदा की रियल टाइम मॉनिटरिंग में सहायता करता है, जबकि उपग्रह डेटा **PM कसिन योजना** के तहत फसल निशिरानी का समर्थन करता है।
 - भारत की अंतरकिष्प पहल सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है, जिससे शासन में समुत्थानशीलन और समावेशता बढ़ेगी।
- अंतरकिष्प नीति और भविष्य के लिये विज्ञन: **भारतीय अंतरकिष्प नीति-2023** नजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर तथा अंतरकिष्प परसिंपत्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आरथिक फ्रेमवरक में एकीकृत करके अंतरकिष्प के लोकतंत्रीकरण पर ज़ोर देती है।
 - वर्ष 2035 तक **राष्ट्रीय अंतरकिष्प स्टेशन** की योजना के साथ, भारत अंतरकिष्प प्रभुत्व के लिये एक मज़बूत रोडमैप तैयार कर रहा है।

भारत के अंतरकिष्प क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- सीमति बजट आबंटन और वित्तीय बाधाएँ: भारत की अंतरकिष्प महत्त्वाकांक्षाएँ अपेक्षाकृत मामूली बजट के कारण सीमति हैं, जिससे बड़े पैमाने की परयोजनाएँ और तकनीकी प्रगतियों परभावित हो रही हैं।
 - यद्यपि भारत अपने नविश पर उच्च लाभ प्राप्त कर रहा है, फरि भी वैश्वकि समकक्षों की तुलना में इसका अंतरकिष्प बजट कम है, जिससे अन्वेषण कार्यक्रम, बुनियादी अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास सीमति हो रहे हैं।

- भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.04% अंतर्राष्ट्रीय पर व्यय करता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अरथव्यवस्था का 0.28% अंतर्राष्ट्रीय पर खर्च करता है।
- ISRO का सत्र 2024-25 के लिये बजट 13,042.75 करोड़ रुपए (करीब 1.95 अरब डॉलर) है। इसके विपरीत, NASA करीब 25 अरब डॉलर के बहुत बड़े बजट के साथ काम करता है।
- **विदेशी प्रशंसितों पर तकनीकी नियन्त्रिता:** प्रगतिके बावजूद, भारत उन्नत सेंसर, प्रणोदन प्रणाली और अर्द्धचालकों जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिये विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर बहुत अधिक नियन्त्रित है।
 - स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास वैश्वकि मानकों से पीछे है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण और उपग्रह नियन्त्रित हो रही है।
 - भारत आयात के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय तकनीक पर भी बहुत हद तक नियन्त्रित है। वर्ष 2024 में भारत का सौर क्षेत्र का आयात 7 बलियन डॉलर तक पहुँच गया। GSLV Mk III के लिये क्रायोजेनिक CE-20 इंजन को विकसित होने में लंबा समय लगा, जिससे स्वदेशी नवाचार में विलंब पर प्रकाश डाला गया।
- **वनियमित और नीतिगत अंतराल:** भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये एक सुदृढ़ कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव है, जो नजीब क्षेत्र की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में बाधा उत्पन्न करता है।
 - यद्यपि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नीति-2023 एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसमें उत्तरवायतिव, बौद्धिक संपदा अधिकार या विवाद समाधान तंत्र का प्रयोग से समावेशन नहीं किया गया है।
 - आउटर सेप्स ट्रटी (वर्ष 1967) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से होने वाले नुकसान के लिये उत्तरवायतिव का प्रावधान करती है, लेकिन भारत के पास ऐसे प्रावधानों को संहिताबद्ध करने के लिये कोई समर्पण अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम नहीं है।
 - स्पष्ट लाइसेंसिंग तंत्र की अनुपस्थितिके कारण नजीब उपग्रहों के प्रक्रियेण में विलंब होता है, जिससे प्रक्रियालय और अग्निकृति कॉर्समॉसेस जैसे स्टार्टअप प्रभावित होते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मलबा और स्थायित्व संबंधी चिह्नाएँ:** भारत द्वारा उपग्रह प्रक्रियेण की संख्या में वृद्धि हो रही है और नियंत्रित उपग्रहों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मलबा बढ़ रहा है, जिससे प्रयोगिक प्रसिंप्टतायों के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है।
 - ऑर्बिट में ISRO की बढ़ती उपस्थितिके साथ-साथ प्रयोगरण संबंधी चिह्नाएँ भी जुड़ी हैं, तथा इसके समाधान की रणनीतियों और मलबा हटाने की व्यवस्थाएँ भी सीमित हैं।
 - वर्ष 2022 तक ऑर्बिट में भारत की 103 सक्रिय या नियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय यान और 114 वस्तुएँ थीं जिन्हें 'अंतर्राष्ट्रीय मलबा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **सीमित रक्षण एवं सुरक्षा तैयारी:** अंतर्राष्ट्रीय सैन्यीकरण के बढ़ते खतरों के बावजूद, रक्षा के लिये भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्षमताएँ वैश्वकि शक्तियों की तुलना में अवधिक्षति हैं।
 - सुदृढ़ उपग्रह रोधी प्रणालयों, अंतर्राष्ट्रीय आधारति पूरव चेतावनी प्रणालयों और समेकति सैन्य-अंतर्राष्ट्रीय नीतिके अभाव के कारण भारत असुरक्षित है।
 - भारत ने अपना पहला ASAT परीक्षण वर्ष 2019 में किया था, जबकि अमेरिका और चीन आकर्षणक संचालन में सक्षमदोहरे उपयोग वाले उपग्रहों को बनाए हुए हैं।
 - भारत का GSAT-7 नौसेना संचार के लिये डिजिटल किया गया है, लेकिन इसमें भूमि-आधारति और अंतर्राष्ट्रीय-आधारति नियंत्रित प्रणालयों के साथ एकीकरण का अभाव है।
- **प्रतभागी प्रयोग और मानव पूँजी की कमी:** कुशल प्रशंसितों का वैश्वकि अंतर्राष्ट्रीय अग्रणीयों की ओर प्रयोग भारत की घरेलू नवाचार क्षमताओं को कमज़ोर करता है।
 - विदेशों में बेहतर वित्तीय पोषण, बुनियादी अवसंरचना और करयित के अवसरों के बावजूद, भारत को उन्नत अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में प्रतभागी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
 - विदेश में अध्ययनरत 70% भारतीय छात्र STEM क्षेत्रों का चयन करते हैं, जिससे भारत में शीर्ष वैज्ञानिकों की प्रतिधिकरण दर कम हो जाती है।
 - भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की NASA और SpaceX की प्रमुख प्रयोजनाओं में योगदान दे रहे हैं, जिनमें मार्स प्रसवियरेंस और स्टारशपि विकास शामिल हैं।
- **अपराधपूर्ण वैश्वकि बाज़ार हस्तेदारी:** वैश्वकि अंतर्राष्ट्रीय अरथव्यवस्था में भारत का योगदान, इसकी लागत-प्रभावी क्षमताओं को देखते हुए, असमान रूप से बहुत कम है।
 - वैश्वकि अंतर्राष्ट्रीय अरथव्यवस्था में भारत की हस्तेदारी 2-3% है। PSLV-C56 जैसे मशिनों ने वाणिज्यिक पेलोड को आकर्षित किया है, लेकिन SpaceX की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों को अधिकतम करने में पीछे रह गए हैं।
- **मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान क्षमताओं में पछिड़ना:** भारत मानव अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण में वैश्वकि अग्रणीयों से पीछे है, तथा उसके पासनारितर मानव मशिन के लिये कोई प्रयोगिक क्षमता नहीं है।
 - यद्यपि गिगनयान मशिन आशाजनक है, लेकिन विकास में विलंब और विदेशी जीवन रक्षक प्रणालयों पर नियन्त्रित भारत की क्षमताओं में अंतर को उजागर करती है।
 - भारत का पहला मानवयुक्त मशिन वर्ष 2025 में प्रस्तावित है, जो चीन से लगभग 20वर्ष पीछे और अमेरिका के अपोलो मशिन से 55 वर्ष पीछे है।
- **बढ़ती भू-राजनीतिकी और सामरकी चुनौतियाँ:** अंतर्राष्ट्रीय में प्रभुत्व के लिये वैश्वकि प्रतिसिप्रदाधा भारत के लिये भू-राजनीतिकी चुनौतियाँ खड़े कर रही हैं, विशेष रूप से चीन की तीव्र प्रगतिके कारण।
 - भारत का नागरिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिकी और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के मामले में आकर्षणक प्रतिसिप्रदाधयों की तुलना में पछिड़ रहा है।
 - चीन का तथिंगांग अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन वर्ष 2022 में चालू हो गया। भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली, NavIC, को चीन के BeiDou की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमित स्वीकृति मिली है।

भारत सतत अंतरकिष्य अन्वेषण सुनिश्चिति करने और अपनी अंतरकिष्य-आधारति क्षमताओं को प्रबल करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- बजटीय आवंटन में वृद्धि और वित्तिपोषण तंत्र में विधिता: मानव अंतरकिष्य उड़ान और गहन अंतरकिष्य अन्वेषण जैसी उच्च प्राथमिकता वाली प्रयोजनाओं को समर्थन देने के लिये सकल घरेलू उत्पाद में अंतरकिष्य क्षेत्र की हसिसेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।
 - दीर्घकालिक निविश आकर्षित करने के लिये सॉवरेन अंतरकिष्य बॉर्ड और सार्वजनिक-नजी योग्य-वित्तिपोषण मॉडल लागू किया जाना चाहयि।
 - अनुसंधान एवं विकास, स्टार्टअप और विद्युतनकारी नवाचार को समर्थन देने के लिये IN-SPACe के अंतर्राष्ट्रीय एकभारतीय अंतरकिष्य कोष की स्थापना की जानी चाहयि।
- सार्वजनिक-नजी सहयोग को बढ़ावा: नजी भागीदारों को ISRO के बुनियादी अवसंरचना, जैसे लॉन्चपैड और परीक्षण सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करके निविश सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP) को संचालित करने की आवश्यकता है।
 - उपग्रह तारामंडल, पुनः प्रयोज्य प्रक्रियेपण वाहनों और चंद्र मशिनों के लिये संयुक्त उद्यम मॉडल विकसित किया जाना चाहयि।
 - IN-SPACe के अंतर्राष्ट्रीय नजी अंतरकिष्य मशिनों के लिये एकल खड़िकी अनुमोदन के साथ नियमित प्राप्ति की ताकत को सरल बनाया जाएगा।
- स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को प्राथमिकता: प्रणोदन प्रणालियों, उपग्रह संचालन में AI और अंतरकिष्य-ग्रेड अर्द्धचालकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समर्पति अंतरकिष्य प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों की स्थापना में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
 - पुनः प्रयोज्य रॉकेट और इन-ऑर्बिट डॉकिंग सिस्टम सहित विद्युतनकारी तकनीकी समाधान बनाने के लिये शैक्षणिक संस्थानों एवं स्टार्टअप्स के साथ सहयोग किया जाना चाहयि।
 - रणनीतिक सवायत्तता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूरण घटकों के लिये आयात प्रतिस्थापन नीतियों को लागू किया जाना चाहयि।
- प्रतभिमा प्रतिधिरण और कार्यबल विकास पर ध्यान केंद्रित करना: विश्वविद्यालयों में विशेष अंतरकिष्य शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने तथा रोबोटिक्स, खगोल भौतिकी एवं एयरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे विषयों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
 - गगनयान और शुक्रयान-1 जैसे उन्नत मशिनों के लिये कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अंतरकिष्य प्रशिक्षण अकादमियाँ स्थापित की जानी चाहयि।
 - अनुसंधान फेलोशिप को प्रोत्साहित किया जाना चाहयि तथा आकर्षक कैरियर मार्गों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रतभिमा को बनाए रखने की भी आवश्यकता है।
- मॉड्यूलर अंतरकिष्य स्टेशन और उन्नत अंतरकिष्य अवसंरचना का विकास: अंतरकिष्य में दीर्घकालिक मानवीय उपस्थितिको बनाए रखने के लिये मॉड्यूलर अंतरकिष्य स्टेशन के निर्माण के लिये प्रतिबिधि होने की आवश्यकता है।
 - सतीश धवन अंतरकिष्य केंद्र को उन्नत करके तथा हाइपरसोनिक व पुनः प्रयोज्य वाहनों के लिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ नए प्रक्रियेपण स्थलों की स्थापना करके प्रक्रियेपण क्षमता का विस्तार किया जाना चाहयि।
 - उपग्रह रखरखाव और मशिन क्षमताओं के विस्तार के लिये कक्ष में सर्वसिंग एवं संयोजन प्रणाली विकसित की जानी चाहयि।
- उपग्रह तारामंडल विकास का सुदृढ़ीकरण: डेटा संप्रभुता को बढ़ाने के लिये NavIC और RISAT जैसे स्वदेशीपृथकी अवलोकन, नेवगिशन और संचार तारामंडल की तैनाती में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
 - आपदा प्रबंधन और सेन्य निगरानी जैसे अनुप्रयोगों के लिये नागरिक एवं रक्षा आवश्यकताओं की पूरत्त हेतुदोहरे उपयोग वाले उपग्रहों को एकीकृत किया जाना चाहयि।
 - नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से उपग्रह निर्माण में नजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहयि।
- अंतरकिष्य स्थायित्व और मलबे के शमन को बढ़ावा देना: अंतरकिष्य मलबे को दैरेक करने और प्रबंधित करने तथा टकरावों को रोकने के लिये अंतरकिष्य स्थितिजिन्य जागूकता (SSA) प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण की आवश्यकता है।
 - D-ऑर्बिटिंग प्रौद्योगिकियों में निविश किया जाना चाहयि तथा मलबे के शमन पर अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाना चाहयि।
 - भारत द्वारा वैश्वकि मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सतत अंतरकिष्य अन्वेषण में नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिये अंतरकिष्य स्थितिजिन्य जागूकता प्रस्तुत की जानी चाहयि।
- सामरक अंतरकिष्य-आधारति रक्षा क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण: उपग्रह जैमर और उपग्रह-रोधी (ASAT) हथयारों सहित अंतरकिष्य-वरिष्ठी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिये रक्षा अंतरकिष्य एजेंसी (DSA) की भूमिका का विस्तार करने की आवश्यकता है।
 - दोहरे उपयोग वाले प्लेटफॉर्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहयि, जो संचार, सामरक प्रयोक्षण और नेवगिशन में भारत के रणनीतिक लाभ को बढ़ाएंगे।
 - राष्ट्रीय रक्षा फ्रेमवरक में अंतरकिष्य प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिये DRDO के साथ सहयोग किया जाना आवश्यक है।
- प्रौद्योगिकी साझाकरण के लिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना: उन्नत प्रौद्योगिकी और साझा संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिये NASA, ESA और रॉसकॉस्मोस जैसी वैश्वकि एजेंसियों के साथ सहयोग को गहन करने की आवश्यकता है।
 - आरटेमसि और ग्रहीय रक्षा पहल जैसे अंतरराष्ट्रीय मशिनों में भाग लेने के लिये द्विपक्षीय समझौतों का लाभ उठाना आवश्यक है।
 - अंतरकिष्य कूटनीति और क्षमता निर्माण के लिये अफ्रीका एवं दक्षिण पूर्व एशिया में उभरते अंतरकिष्य राष्ट्रों के साथ संबंधों को मज़बूत किया जाना चाहयि।
- एक व्यापक अंतरकिष्य अधिनियम की स्थापना: अंतरकिष्य गतविधियों को नियंत्रित करने के लिये एक सुदृढ़ कानूनी फ्रेमवरक प्रदान करने, लाइसेंसिं, बौद्धिक संपदा अधिकारों और विविद समाधान पर स्पष्टता सुनिश्चिति करने के लिये एक समर्पति अंतरकिष्य अधिनियम का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है।
 - बाह्य अंतरकिष्य संधि जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत भारत के दायतिव को संहतिबद्ध किया जाना चाहयि तथा अंतरकिष्य उपकरणों में ईज़ ऑफ छुइग बिज़िनेस को बढ़ावा दिया जाना चाहयि।
 - विदेशी निविश को आकर्षित करने के लिये नजी क्षेत्र की क्षतपूरिति के लिये प्रावधान शामलि किया जाना चाहयि।
- अंतरकिष्य प्रौद्योगिकी के सामाजिक-आर्थिक अनुप्रयोगों का विस्तार: प्रशिद्ध कृषि, जल संसाधन प्रबंधन और शहरी नियोजन के लिये उपग्रह-आधारति भू-स्थानकि डेटा का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

- भुवन जयोपोर्टल जैसे कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाकर इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये टेलीमेडिसिनि और ई-शक्तिका को शामिल किया जाना चाहयि।
- परविरतनकारी प्रभाव के लिये **PM-कसिन, डिजिटल इंडिया** और **स्मार्ट सटी** जैसे राष्ट्रीय मशिनों में अंतरकिंष परसिंपत्तयों को एकीकृत किया जाना चाहयि।
- **पुनः प्रयोज्य और हाइपरसोनिक प्रक्षेपण प्रणालयों का निर्माण:** प्रक्षेपण लागत को कम करने और मशिन आवृत्ति को बढ़ाने के लिये पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों (**RLV**) के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है।
 - उपग्रहों और अन्तरिक्ष पेलोड की तीव्र तैनाती को समर्थन देने के लिये हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रणालयों में नविश करना आवश्यक है।
 - नेक्स्ट जनरेशन की प्रक्षेपण क्षमताओं के लिये सक्रैमजेट और सपेसप्लेन जैसी परौद्योगिकियों को संचालित करने हेतु नजी फरमों के साथ सहयोग किया जाना चाहयि।
- **अंतरकिंष आधारित उद्यमता को बढ़ावा देना:** उपग्रह निर्माण, डेटा विश्लेषण और पेलोड विकास जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप और MSME को प्रोत्साहित करने के लिये एक राष्ट्रीय अंतरकिंष नवाचार फ्रेमवरक तैयार करने की आवश्यकता है।
 - उद्यमियों के लिये ISRO की सुविधाओं और मैटरशापि कार्यक्रमों के माध्यम से इन्क्र्यूबेशन सहायता प्रदान की जानी चाहयि।
 - युवा-प्रेरित विचारों और समाधानों का लाभ उठाने के लिये हैकथॉन और अंतरकिंष नवाचार चुनौतयों का शुभारंभ किया जाना चाहयि।

निष्कर्ष:

भारत का अंतरकिंष कार्यक्रम एक प्रविरतनकारी मोड़ पर है, जो प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति, रणनीतिक सहयोग और सार्वजनिक-नजी तालमेल के बढ़ते पारस्थितिकी तंत्र द्वारा चाहिनति है। यद्यपि फिंडिंग, विनियोगिक फ्रेमवरक और स्वदेशी क्षमता विकास के मामले में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फरि भी भारत के लागत प्रभावी नवाचार एवं महत्वाकांक्षी मशिन इसे एक उभरती हुई वैश्वकि अंतरकिंष शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं।

प्रश्न:

प्रश्न. “अंतरकिंष प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति में वैश्वकि भू-राजनीति और सामाजिक-आरथकि विकास में इसकी भूमिका को पुनः प्रभावित करने की क्षमता है।” अंतरकिंष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासलि करने में भारत के लिये चुनौतयों और अवसरों पर चर्चा कीजियि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न

प्रश्न 1. भारत की अपना स्वयं का अंतरकिंष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरकिंष कार्यक्रम को यह कसि प्रकार लाभ पहुँचाएगी? (2019)

प्रश्न 2. अंतरकिंष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजियि। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक-आरथकि विकास में कसि प्रकार सहायक हुआ है? (2016)

प्रश्न 3. भारत के तीसरे चंद्रमा मशिन का मुख्य कार्य क्या है जसि इसके पहले के मशिन में हासलि नहीं किया जा सका? जनि देशों ने इस कार्य को हासलि कर लिया है उनकी सूची दीजियि। प्रक्षेपिति अंतरकिंष यान की उप-प्रणालयों को प्रस्तुत कीजियि और विक्रम साराभाई अंतरकिंष केंद्र के 'आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण' की उस भूमिका का वर्णन कीजियि जसिने श्रीहरकिंटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। (2023)